गन्ने की रकम चुकाने के लिए ₹7,000 करोड़ देगी सरकार!

सरकार कैबिनेट कमेटी ऑन इकनॉमिक अफेयर्स (CCEA) की मीटिंग में इस बारे में फैसला कर सकती है, पहले भी ₹1,500 करोड़ की सब्सिडी का किया था ऐलान

[पीटीआई | नई दिल्ली]

गन्ने की बकाया रकम 22,000 करोड़ रुपये से अधिक होने से सरकार की चिंता बढ़ गई है। इस समस्या से निपटने के लिए सरकार चीनी मिलों को 7,000 करोड़ रुपये से अधिक का राहत पैकेज दे सकती है। सूत्रों ने बताया कि कैबिनेट कमेटी ऑन इकनॉमिक अफेयर्स (CCEA) की मंगलवार को होने वाली मीटिंग में इस बारे में फैसला किया जा सकता है। सरकार ने मिलों को गन्ने की कीमत का भुगतान करने में मदद के लिए पिछले महीने 1,500 करोड़ रुपये की प्रॉडक्शन से जुड़ी सब्सिडी देने की घोषणा की थी। चीनी की कीमतों में बड़ी गिरावट के कारण मिलों की वित्तीय स्थिति बहुत खराब है और इस वजह से उन्हें गन्ना किसानों का भुगतान करने में मुश्किल हो रही है। उत्तर प्रदेश में गन्ने की सबसे अधिक 12,000 करोड़ रुपये की रकम बकाया है। देश में उत्तर प्रदेश गन्ने का सबसे अधिक उत्पादन करता है।

फूड मिनिस्ट्री ने चीनी का 30 लाख टन का बफर स्टॉक बनाने का प्रपोजल दिया है। इसके अलावा मिनिस्ट्री ने चीनी का न्यूनतम एक्स मिल प्राइस लगभग 30 रुपये प्रति किलोग्राम तय करने, चीनी को जारी करने की मासिक व्यवस्था और मिलों पर स्टॉक लिमिट लगाना दोबारा शुरू करने जैसे सुझाव दिए हैं। अभी चीनी का एक्स मिल प्राइस 25.60-26.22 रुपये प्रति किलोग्राम है, जो प्रॉडक्शन की कॉस्ट से भी कम है। मुश्किलों का सामना कर रही शुगर इंडस्ट्री की मदद के लिए पेट्रोलियम मिनिस्ट्री ने एथनॉल की नई कैपेसिटी तैयार करने के लिए चीनी मिलों को 4,500 करोड़ रुपये पर 6 पर्सेंट की इंटरेस्ट सब्सिडी देने का प्रपोजल रखा है। इस स्कीम के तहत मिलों को कर्ज के भुगतान के लिए पांच वर्ष का समय दिया जाएगा। पेट्रोलियम मिनिस्ट्री एथनॉल की कीमत बढ़ाने पर भी विचार कर रही है। इससे मिलों को कुछ राहत मिलेगी। देश में चीनी की गिरती कीमतों पर लगाम लगाने के लिए केंद्र ने चीनी पर इम्पोर्ट ड्यूटी दोगुनी कर 100 पर्सेंट की थी और एक्सपोर्ट ड्यूटी समाप्त कर दी थी। रेटिंग एजेंसी इकरा ने कहा है कि चीनी की सप्लाई अधिक रहने से इसकी कीमतों पर दबाव जारी रहेगा। चीनी के ग्लोबल प्राइसेज कमजोर होने के कारण केंद्र सरकार की 20 लाख टन चीनी के एक्सपोर्ट की घोषणा के बावजूद देश में इसकी कीमतों पर दबाव जारी रहेगा। शुगर ईयर 2018 में चीनी का प्रॉडक्शन बढ़कर 3.1 करोड़ टन से अधिक हो सकता है।

इकरा रेटिंग्स के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट और ग्रुप हेड, सब्यसाची मजूमदार ने बताया कि महाराष्ट्र, उत्तर कर्नाटक और यूपी का उत्पादन बढ़ने में बड़ा योगदान होगा। उन्होंने कहा, '2018 में चीनी की खपत बढ़कर लगभग 2.5 करोड़ टन पर पहुंचने की उम्मीद है।' इकरा का कहना है कि 20 लाख टन का एक्सपोर्ट होने के बाद भी देश में अगले सीजन के लिए चीनी का करीब 25.3 लाख टन का अतिरिक्त स्टॉक मौजूद होगा।

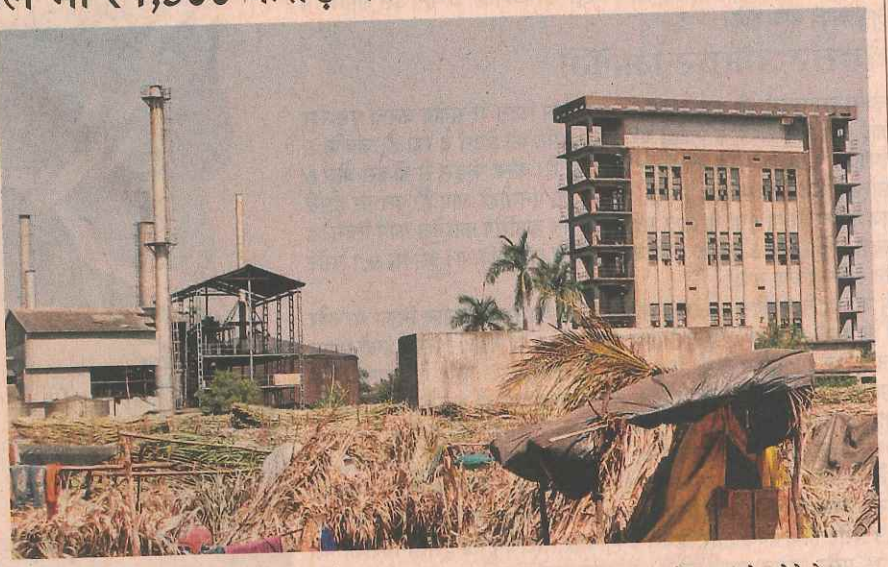

यूपी में सबसे ज्यादा बकाया

- उत्तर प्रदेश में गन्ने की सबसे अधिक 12,000 करोड़ रुपये की रकम बकाया है
- देश में उत्तर प्रदेश गन्ने का सबसे अधिक उत्पादन करता है

ET (Hindi)
5/6/2018